

## तटीय क्षरण से वसिथापति समुदायों हेतु मसौदा नीति

### प्रलिस के लयि:

NDMA, NDRF, तटीय क्षरण, 15वें वतित आयोग की रपिरट ।

### मेन्स के लयि:

तटीय क्षरण से वसिथापति समुदायों हेतु मसौदा नीति

## चर्चा में क्योँ?

**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** ने नदी और तटीय क्षरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु भारत की पहली राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों और शोधकर्त्ताओं से इनपुट प्राप्त किये ।

- गृह मंत्रालय ने NDMA को वर्ष 2021 के लिये **15वें वतित आयोग** की रपिरट के आधार पर एक नीति का मसौदा तैयार करने का नरिदेश दिया था ।
- अभी तक देश में अधिकांश नीतियाँ केवल बाढ़ और चक्रवात जैसी अचानक तेज़ी से शुरू होने वाली आपदाओं के बाद वसिथापन को संबोधित करती हैं ।

## 15वें वतित आयोग की रपिरट की सफारिशें:

- इसने पहली बार **जलवायु परिवर्तन** के कारण बढ़ते खतरे के मद्देनज़र नदी और तटीय क्षरण से वसिथापति लोगों के लिये पुनर्वास और उनके पुनर्स्थापन पर ज़ोर दिया था ।
- इसने वर्ष 2021-26 के लिये 1,500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के तहत तटीय क्षरण को रोकने हेतु शमन उपायों की शुरुआत की ।
- क्षरण से प्रभावित वसिथापितों के पुनर्वास के लिये यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के तहत इसी अवधि के लिये 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करता है ।
- इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कशियों को बना देरी किये शमन और पुनर्वास परियोजनाओं के लिये समय-सीमा का पालन करना चाहिये, NDRF एवं NDMF के तहत परियोजनाओं को इस तरह से मंजूरी दी जानी चाहिये कि उन्हें आयोग की अधनिरिणय अवधि के भीतर पूरा कया जा सके ।

## मसौदा नीति की प्रमुख वशिषताएँ:

- वतित आवंटन:
  - दोनों नधियों (NDRF और NDMF) के लिये राज्य सरकारों को लागत-साझाकरण के आधार पर संसाधनों का लाभ उठाना होगा, जो तटीय एवं नदी क्षरण से जुड़े शमन और पुनर्वास की लागत में 25% का योगदान देगा ।
  - हालाँकि पूर्वोत्तर राज्यों को राज्य नधि का केवल 10% एकत्रित करना होगा ।
  - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शमन और पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय स्तर पर NDRF एवं NDMF के तहत आवंटन तथा खर्चों का समन्वय करेगा ।
- नोडल एजेंसी:
  - ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) अन्य ज़िला एजेंसियों और एक वशिषिट पंचायत-स्तरीय समिति के माध्यम से सहायता प्राप्त करने हेतु उपायों को लागू करने के लिये नोडल एजेंसी होगी ।
  - DDMA शमन और पुनर्वास योजनाएँ तैयार करेगा और उन्हें SDM को सौंप देगा, जहाँ प्रस्तावित उपायों का NDMA द्वारा मूल्यांकन कया जाएगा और अंत में गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा ।
  - इसके पश्चात् इस मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति वतित वतितरण की मंजूरी प्रदान करेगी ।

- **जोखमि संबंधी वसितृत आकलन:**
  - राष्ट्रीय तट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय जल आयोग आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जोखमि संबंधी वसितृत आकलन और **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र** के पास उपलब्ध **उच्च-रिज़ॉल्यूशन LiDAR डेटा SDMA** को उपलब्ध कराना होगा।
  - इन्हें NDMA द्वारा ईजी-टू-एक्सेस भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- **तटीय और नदी के कषरण का मानचित्रण:**
  - यह नीति तटीय और नदी के कषरण के प्रभावों का मानचित्रण करने एवं प्रभावति तथा कमज़ोर समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली वविधि चुनौतियों का एक डेटाबेस तैयार करने पर ज़ोर देती है।
- **प्रभाव और सुभेद्यता आकलन:**
  - यह मसौदा नीति समय-समय पर तटीय और नदी कषरण से प्रभावति क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों तथा सुभेद्यता आकलन की भी सफ़िरशि करती है, जसि SDMA द्वारा राज्य के वभिगों एवं DDMA के समन्वय से संचालति कयि जाएगा।

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण (NDMA):

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण भारत में **आपदा प्रबंधन के लयि शीर्ष वैधानकि नकिय है।**
- इसका **औपचारकि रूप से गठन 27 सतिबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 के तहत** हुआ जसिमें प्रधानमंत्री (अध्यकष) और नौ अन्य सदस्य होंगे तथा इनमें से एक सदस्य उपाध्यकष पद पर आसीन होता है।
- आपदा प्रबंधन की प्राथमकि ज़मिमेदारी संबंधति राज्य सरकार की होती है। हालाँकि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति केंद्र, राज्य और ज़लि, सभी के लयि एक सक्षम वातावरण बनाती है।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. आपदा प्रबंधन में पूरववर्ती प्रतकिरयितमक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ कयि गए अभनूितन उपायों की वविचना कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2020)

प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण (एनडीएमए) के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखण्ड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लयि अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2016)

प्रश्न. सूखे को उसके स्थानकि वसितार, कालकि अवधि, मंथर प्रारंभ और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृषटि से आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण (एनडीएमए) के सतिबर 2010 के मार्गदर्शी सिधितों पर ध्यान केंद्रति करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावति दुषप्रभावों से नपिटने के लयि तैयारी की कार्यवधियिों पर चर्चा कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2014)

**स्रोत: डाउन टू अर्थ**